नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 213
दि. 07.05.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

वंदे मातरम को मिला राष्ट्रगीत से आगे विशेष दर्जा, अपमान पर सख्त दंड के साथ नई राष्ट्रीय व्यवस्था लागू

नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा संवैधानिक और सांस्कृतिक निर्णय देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। वंदे मातरम को अब राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दर्जा देते हुए इसे राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण के दायरे में लाया गया है। इस फैसले के बाद अब इसके सम्मान और अपमान से जुड़े नियम उसी तरह लागू होंगे जैसे वर्तमान में राष्ट्रगान "जन गण मन" के लिए लागू हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

इस निर्णय के साथ ही गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें वंदे मातरम के आधिकारिक उपयोग, गायन के प्रोटोकॉल और इसके सम्मान से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस गीत के गायन में बाधा डालता है या उसका अपमान करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दोबारा अपराध करने की स्थिति में सख्त दंड का प्रावधान भी रखा गया है।

सरकार ने इस बदलाव को भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सम्मान से जोड़ते हुए इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस ऐतिहासिक गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर से भी जोड़ा है। यह निर्णय कैबिनेट की उस बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा।

संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर लागू नियम अब वंदे मातरम पर भी समान रूप से लागू होंगे। इसका उद्देश्य

राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को और अधिक संस्थागत रूप देना बताया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गर्व की भावना को मजबूत करेगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार, वंदे मातरम का पूर्ण आधिकारिक संस्करण, जिसमें छह श्लोक शामिल हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है, अब प्रमुख राजकीय समारोहों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इन समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रम, और अन्य औपचारिक राजकीय आयोजन शामिल हैं। इन अवसरों पर इसे राष्ट्रगान से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों शामिल हैं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान। दोनों अवसरों पर उपस्थित लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे सम्मान के प्रतीक के रूप में सावधान मुद्रा में खड़े रहें। यह नियम इस विचार को मजबूत करता है कि दोनों ही राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान के समान स्तर पर हैं।

इसके अलावा, सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम के गायन को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में इसके नियमित गायन को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि युवाओं में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान विकसित हो सके। यह पहल विशेष रूप से छात्रों में सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई है।

गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि जब वंदे मातरम का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाएगा, तो उसकी शुरुआत ढोल या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से की जाएगी, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ेगी। यह प्रोटोकॉल इसे एक औपचारिक और सम्मानजनक राष्ट्रीय प्रस्तुति के रूप में स्थापित करता है।

हालांकि, सरकार ने व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट भी दी है। उदाहरण के लिए, सिनेमा हॉल या फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान यदि वंदे मातरम फिल्म के साउंडट्रैक का हिस्सा है, तो दर्शकों को खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मनोरंजन स्थलों पर दर्शकों का अनुभव बाधित न हो और किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।

इस पूरे निर्णय को लेकर देशभर में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थकों का मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाएगा, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे कानूनी और व्यावहारिक दृष्टि से एक जटिल निर्णय भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान आवश्यक है, लेकिन उनके अनुपालन को लेकर स्पष्ट और संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए।

फिर भी, सरकार का रुख स्पष्ट है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की भावना और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसे कानूनी संरक्षण देना उस ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने का प्रयास है, जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कुल मिलाकर यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक और संवैधानिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। यह केवल एक नियम परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और गौरव को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर दिखाई दे सकता है।

केरल में सत्ता का ताज किसे, राहुल गांधी का 'विधायक प्रथम' फॉर्मूला बना निर्णायक

तिरुअनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक इन दिनों कांग्रेस खेमे में एक ही सवाल गूंज रहा है—केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत ने जहां पार्टी को नई ऊर्जा दी है, वहीं अब नेतृत्व चयन को लेकर अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं राहुल गांधी, जिन्होंने साफ संकेत दिया है कि इस बार मुख्यमंत्री के चयन में "हाईकमान संस्कृति" नहीं, बल्कि "विधायक प्रथम" का सिद्धांत लागू होगा।

कांग्रेस नेतृत्व इस बार किसी भी तरह की जल्दबाजी या विवाद से बचना चाहता है। पार्टी को पंजाब जैसे पिछले अनुभवों से सीख मिली है, जहां विधायकों की राय के विपरीत लिया गया फैसला भारी पड़ा था। इसी वजह से राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि केरल में मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, जिसे अधिकांश विधायक स्वीकार करेंगे। इसके लिए पर्यवेक्षकों के रूप में अजय माकन और मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी दी गई है, जो विधायकों से बातचीत कर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे प्रमुख नाम रमेश चेन्नीथला का माना जा रहा है। संगठन और सरकार दोनों में उनका लंबा अनुभव उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। वे पूर्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के भीतर एक संतुलित और भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। गांधी परिवार, खासकर सोनिया गांधी के करीबी होने के कारण भी उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उन्होंने पहले भी कई मौकों पर अपनी दावेदारी पीछे रखी है, ऐसे में इस बार उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

दूसरी ओर, वीडी सतीशन एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं, जो युवा ऊर्जा और आक्रामक राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने वाम मोर्चे के खिलाफ मजबूत विपक्ष खड़ा किया और जनता के बीच अपनी पहचान बनाई। उनका अपेक्षाकृत युवा होना और जमीनी पकड़ उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। हालांकि, हाल ही में उनसे जुड़े कुछ विवाद—जैसे मंगलुरु यात्रा और चार्टर्ड फ्लाइट प्रकरण—उनकी राह में कुछ बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। पार्टी नेतृत्व इन मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेना चाहता है।

तीसरा बड़ा नाम केसी वेणुगोपाल का है, जो वर्तमान में कांग्रेस संगठन के महासचिव हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक समझ पार्टी के लिए बेहद अहम है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन रही है। दिल्ली में पार्टी का एक वर्ग चाहता है कि उन्हें केरल भेजा जाए, जिससे संगठन में नई जगह बन सके। हालांकि, यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार को दिल्ली से दूर नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा, विधायकों के बीच भी एक "स्थानीय चेहरे" की मांग अधिक मजबूत दिखाई दे रही है।

इस पूरी तस्वीर में एक और दिलचस्प पहलू है—लोकसभा सांसदों की भूमिका। शशि थरूर का नाम भी चर्चा में जरूर है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनकी राह आसान नहीं दिखती। थरूर और वेणुगोपाल दोनों ही संसद के सदस्य हैं, और यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उन्हें इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ना होगा। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस किसी भी तरह का उपचुनाव जोखिम लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि संसद में हर सीट का महत्व है और विपक्ष की रणनीति में कोई भी कमजोरी भारी पड़ सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की भूमिका निर्णायक बनी हुई है, लेकिन उनकी रणनीति पारंपरिक "हाईकमान फैसले" से अलग नजर आ रही है। कर्नाटक और तेलंगाना में अपनाए गए मॉडल की तरह वे यहां भी विधायकों की राय को सर्वोपरि रख रहे हैं। यह तरीका एक तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में किसी भी असंतोष या बगावत की संभावना को भी कम करता है। कांग्रेस के भीतर यह भी समझ है कि केरल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में नेतृत्व चयन का फैसला केवल व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल की स्थिरता और सफलता तय करेगा। यदि मुख्यमंत्री के चयन में सभी गुटों की सहमति बन जाती है, तो सरकार को मजबूत आधार मिलेगा। लेकिन यदि निर्णय में असंतुलन हुआ, तो इसका असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल, पर्यवेक्षक विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी राय को एकत्रित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया केवल औपचारिक नहीं, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यही राय अंतिम फैसले का आधार बनेगी। दिल्ली में बैठा नेतृत्व भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अंतिम निर्णय उसी दिशा में जाएगा, जहां से सबसे ज्यादा समर्थन दिखाई देगा।

असम में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू, हिमंत बिस्व सरमा ने सौंपा इस्तीफा लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में संभाली जिम्मेदारी

गुवाहाटी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असम में नई सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य की सत्ता परिवर्तन की दिशा साफ होती नजर आ रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है।

राजभवन में हुई इस औपचारिक प्रक्रिया के दौरान सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि, संवैधानिक परंपरा के अनुसार नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य जारी रखने का अनुरोध किया गया है। इस भूमिका में वे केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे, जबकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सरमा ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, ताकि वे असम की नई सरकार के गठन के साक्षी बन सकें। यह संकेत है कि पार्टी इस शपथ ग्रहण को एक बड़े राजनीतिक और प्रतीकात्मक आयोजन के रूप में देख रही है।

सरकार गठन की प्रक्रिया के अगले चरण में अब विधायक दल की बैठक अहम भूमिका निभाएगी। इसी बैठक में नया नेता चुना जाएगा, जो राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। सरमा ने जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के नेता नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जो विधायक दल की बैठक की निगरानी करेंगे और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि वे जल्द ही जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे और जैसे ही नव निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाने का निर्देश मिलेगा, उसे तुरंत आयोजित किया जाएगा। इसके बाद विधायक दल अपना नेता चुनेगा और उसी के आधार पर शपथ ग्रहण समारोह की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम को असम की राजनीति में एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। हिमंत बिस्व सरमा पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा रहे हैं और उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद सत्ता परिवर्तन की यह प्रक्रिया एक नए चरण की शुरुआत मानी जा रही है।

राज्य में सरकार गठन की यह प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि चुनाव परिणाम आने के बाद संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से एक व्यवस्थित ढंग से सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करती हैं। इस्तीफे से लेकर कार्यवाहक सरकार, फिर विधायक दल की बैठक और अंततः नए मुख्यमंत्री का चयन—यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती को दिखाती है।

फिलहाल, असम में राजनीतिक स्थिति स्थिर बनी हुई है और प्रशासनिक कामकाज सामान्य रूप से जारी है। नई सरकार के गठन तक हिमंत बिस्व सरमा ही राज्य की बागडोर संभालते रहेंगे, जबकि राजनीतिक स्तर पर अगला बड़ा कदम विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को राहत नहीं-संविधानिक संतुलन पर गहराया विमर्श

नई दिल्ली में देश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण मामला इन दिनों न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गंभीर बहस का केंद्र बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने से स्पष्ट इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार की समय मांगने वाली दलील को खारिज कर दिया है। अदालत का यह रुख इस बात का संकेत है कि वह इस मुद्दे को केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल आत्मा से जुड़ा प्रश्न मान रही है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने अन्य मामलों में व्यस्तता का हवाला देते हुए समय मांगा, तो अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे टाला नहीं जा सकता। अदालत की इस टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ सुनना चाहती है।

सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी तब सामने आई, जब सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि वे फिलहाल सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामले में नौ जजों की संविधान पीठ के सामने व्यस्त हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि वर्तमान मामला उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत थी कि अदालत चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए

कितना केंद्रीय मानती है।

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि दिसंबर 2023 में पारित उस कानून से जुड़ी है, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया है। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा था कि जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और संतुलित रहे।

हालांकि, नए कानून में इस व्यवस्था को बदलते हुए मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। यही वह बिंदु है, जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस बदलाव से चयन समिति में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाएगा और इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका से जुड़ा है, इसलिए हितों के टकराव की स्थिति से बचने के लिए उनका इस बेंच का हिस्सा बने रहना उचित नहीं होगा। यह कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अब यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने विचाराधीन है, जो लगातार इस पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी बहस तय समय सीमा में पूरी करें, जिससे मामले का जल्द निपटारा किया जा सके। यह भी संकेत है कि अदालत इस मुद्दे को लंबित नहीं रखना चाहती और जल्द से जल्द स्पष्टता लाने के पक्ष में है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को तेज कर दिया है। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रीढ़ माना जाता है। यदि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो इसका सीधा असर लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है।

कानून के समर्थकों का तर्क है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नियुक्ति प्रक्रिया को अपने अनुसार निर्धारित करे और इसमें कार्यपालिका की भूमिका स्वाभाविक है। वहीं, विरोध करने वालों का कहना है कि यदि चयन समिति में संतुलन नहीं रहेगा, तो नियुक्तियों में पक्षपात की संभावना बढ़ सकती है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इस बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सुनवाई टालने से इनकार यह दर्शाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। अदालत का यह रुख न केवल इस मामले के परिणाम को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को भी दिशा देगा। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और उसमें दिए जाने वाले फैसले पर पूरे देश की नजर रहेगी। यह केवल एक कानून की वैधता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और पारदर्शिता किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

संपादकीय

गंगोत्री से गंगासागर तक कमल खिला

बंगाल में भाजपा का खेला काम कर गया। ऐसा भी नहीं है कि तीन बार से सत्ता पर काबिज बंगाल की शेरनी ममता से जनता का मोहभंग हाल-फिलहाल की घटना है। भाजपा ने दशकों से आक्रामक रणनीति से चुनावी तैयारी की है। केंद्र सरकार के तमाम संसाधनों का गाहे-बगाहे प्रयोग किया। बंगालियों को रास आने वाले तमाम विमर्श गढ़े और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिये लाखों मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। मोदी-शाह की आक्रामक रणनीति के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ता स्तर पर गहन अभियान चले। फिलहाल, गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा का शासन हो गया है। गंगा के प्रवाह के साथ बहने वाले झारखंड को छोड़ दें तो बाकी राज्य भगवामय हैं। जहां बंगाल में पहली बार कमल खिला है, वहीं तमिलनाडु में थलापति के नाम से चर्चित सुपरस्टार विजय की दमदार एंट्री हुई है। उन्होंने भी परंपरागत राजनीतिक दलों की घोषणाओं से बढ़कर लोकलुभावने वायदे किए हैं। फलतः दो ध्रुवीय द्रविड़ राजनीति सत्ता से बाहर हुई है। स्टालिन न केवल हारे हैं, बल्कि उनकी सरकार भी गई। छह दशक बाद राज्य में गैर द्रविड़ियन सरकार बनने जा रही है। हालांकि, अभी सत्ता में आने के लिये टीवीके को गठबंधन का सहारा लेना होगा। भाजपा के लिये भी पत्ते खेलने के अवसर हैं। जहां बंगाल, केरलम व तमिलनाडु में सत्ता विरोधी लहर में सरकारें धराशायी हुई हैं,वहीं असम में भाजपा की हैट्रिक बनी है। हेमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने भरपूर बहुमत पाया है। पुडुचेरी में फिर एनडीए सत्ता पर काबिज हुआ है। लेकिन भाजपा की इस जीत की खुशी के बीच केरलम में कांग्रेस नीत गठबंधन की वापसी हुई है। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम वाम दलों के लिये दुःस्वप्न ही साबित हुए हैं, केरलम में उनका आखिर गढ़ भी हाथ से निकल गया है। हालांकि, केरलम में भाजपा ने तीन व तमिलनाडु में एक सीट जीतकर हिंदी बेल्ट की पार्टी के ठप्पे से मुक्त होने का प्रयास किया है।

इन विधानसभा चुनाव परिणामों का निष्कर्ष यह भी है कि अब क्षेत्रीय क्षत्रपों की मुखर आवाज कुंद हो गई है। जहां ममता,स्टालिन व विजयन सत्ता से बाहर हो गए हैं, वहीं शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक का प्रभाव भी फीका हुआ है। वर्तमान विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश का 72 फीसदी भूभाग व 78 फीसदी आबादी भाजपा शासित है। अनुमान है कि अब भाजपा 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर मुखर हो सकती है। कयास बंगाल को लेकर भी हैं कि वहां आंदोलनों के अगुवा रहे सुवेंदु अधिकारी को सत्ता की बागडोर सौंपी जाएगी, या भाजपा कोई चौंकाने वाली पहल करती है। बहरहाल, बंगाल में भाजपा ने आक्रामक चुनावी रणनीति से महज 8 फीसदी वोट प्रतिशत की वृद्धि से 131 सीटें बढ़ा ली हैं। इतना ही नहीं टीएमसी के मजबूत गढ़ों में 53 सीटें कब्जा ली हैं। बहरहाल, पहले से ही कमजोर विपक्ष को यह परिणाम बड़ा झटका है। कांग्रेस व वाम दलों से किनारा करके चलने की ममता की महत्वाकांक्षी कोशिश का लाभ भाजपा को मिला है। हां, इतना जरूर है कि दक्षिण भारत में पकड़ बनाने के लिये भाजपा को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बार उसे केरल की तीन व तमिलनाडु की एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं केरलम में वाम मोर्चे के अंतिम किले का ध्वस्त होना और लगातार टकराव के मूड में रहने वाले स्टालिन की विदाई उसका उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बहरहाल- ममता, विजयन और स्टालिन की हार से संकेत मिलता है कि कांग्रेस विपक्ष के कमजोर 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व करती रहेगी। लेकिन भाजपा को आने वाले समय में पंजाब में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, जहां आम आदमी पार्टी व कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के प्रयासों में लगे हैं। बहरहाल,विगत में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रखने वाले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान उपजी कटुता को नियंत्रित करने के प्रयास बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करने होंगे। निस्संदेह, लोकतंत्र में हिंसा की कोई भूमिका नहीं स्वीकारी जानी चाहिए। विश्वास करें कि नयी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध को संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

एक दौर का चुनाव और अनेक निष्कर्ष

> "नतीजों से स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक किला स्थायी नहीं। मतदाता अब अधिक सजग और निर्णायक है और चुनाव अब केवल भावनात्मक मुद्दों से नहीं जीते जाते। 2027 के चुनाव इस यथार्थ की पुष्टि करेंगे।

हालिया विधानसभा चुनावों ने राजनेताओं को एक बार फिर यह याद दिलाया है कि यहां कोई भी किला स्थायी नहीं होता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत और तृणमूल कांग्रेस की पराजय ने उस धारणा को तोड़ दिया है कि मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व अजेय होता है। ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ के बावजूद सत्ता परिवर्तन यह बताता है कि मतदाता अब नेतृत्व की छवि से आगे बढ़कर ठोस परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है।

दक्षिण में तमिलनाडु का परिणाम शायद सबसे दिलचस्प है, जहां अभिनेता विजय की पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट बनना केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि राजनीतिक रिक्तता में नए विकल्प की मांग का प्रमाण है। यह उस बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के बीच मतदाता नए नेतृत्व को परखने के लिए तैयार है।

केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति यह दिखाती है कि वैचारिक रूप से सजग माने जाने वाले राज्य भी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं, यदि मतदाता को विकल्प विश्वसनीय लगता है। इसके विपरीत असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत यह साबित करती है कि जहां शासन मॉडल स्वीकार्य है, वहां एंटी-इंकम्बेंसी भी समाप्त हो जाती है। पुदुचेरी में भाजपा गठबंधन की दूसरी बार सरकार इसी निरंतरता का एक और उदाहरण है। इन पांच राज्यों के नतीजों से साफ है कि भारत में अब कोई एक राजनीतिक ट्रेंड नहीं, बल्कि कई समानांतर ट्रेंड चल रहे हैं।

इन नतीजों को यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, तो तीन बड़े ट्रेंड सामने आते हैं।

पहला है चयनात्मक एंटी-इंकम्बेंसी। यानी हर राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जहां सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक है, वहां मतदाता उसे दोहराने में संकोच नहीं करता। दूसरा है क्षेत्रीय दलों को चुनौती। यहां बंगाल का परिणाम बताता है कि मजबूत क्षेत्रीय दल भी चुनौती से परे नहीं हैं। और तीसरा है नए विकल्पों की स्वीकार्यता। तमिलनाडु में 'सिने स्टार' से 'सियासी स्टार' बने विजय का उभार यह दर्शाता है कि मतदाता नए चेहरों को मौका देने के लिए तैयार है।

इन चुनावों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भारतीय राजनीति अब एकल नैरेटिव से संचालित नहीं होती। बंगाल में सत्ता परिवर्तन, तमिलनाडु में नए विकल्प का उभार, केरल में वामपंथियों की शिकस्त और कांग्रेस की वापसी तथा असम व पुदुचेरी में स्थिरता- यह विविधता इस बात का संकेत है कि मतदाता अब अधिक सूक्ष्म स्तर पर निर्णय ले रहा है। वह राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अंतिम फैसला स्थानीय अनुभव और नेतृत्व की विश्वसनीयता के आधार पर करता है।

इन संकेतों की असली परीक्षा 2027 में होगी, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। समय-सीमा के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव अगले वर्ष की पहली तिमाही में संभावित हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में वर्ष के अंत में मतदान हो सकता है। लेकिन यह केवल चुनावी कैलेंडर नहीं है। यह उन राजनीतिक प्रवृत्तियों की परीक्षा है, जो अभी उभरकर सामने आई हैं।

उत्तर प्रदेश का चुनाव इन सभी ट्रेंड्स का सबसे बड़ा परीक्षण होगा। यहां का जनादेश केवल राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दिशा भी तय करता है। सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाएं, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे कारक मिलकर यहां चुनावी परिणाम तय करते हैं। बंगाल का उदाहरण दिखाता है कि सत्ता परिवर्तन संभव है, जबकि असम का उदाहरण बताता है कि निरंतरता भी संभव है। उत्तर प्रदेश इन दोनों के बीच संतुलन का मैदान होगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह परंपरा जारी रहेगी या मतदाता प्रदर्शन के आधार पर स्थिरता को प्राथमिकता देगा। गुजरात लंबे समय से एक राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण रहा है। लेकिन बंगाल के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक गढ़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यदि विपक्ष संगठित होता है और स्थानीय मुद्दे उभरते हैं, तो यहां भी मुकाबला रोचक हो सकता है।

पंजाब में राजनीति हमेशा परिवर्तनशील रही है। यहां 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब देगा कि क्या मतदाता बार-बार बदलाव चाहता है या अब स्थिर शासन की तलाश में है। केरल के नतीजों ने यह संकेत दिया है कि यदि विकल्प विश्वसनीय हो, तो मतदाता बदलाव से पीछे नहीं हटता। गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में चुनावी परिणाम अक्सर गठबंधन और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करते हैं। पुदुचेरी के नतीजों ने यह दिखाया है कि छोटे राज्यों में भी निरंतरता संभव है, यदि राजनीतिक प्रबंधन प्रभावी हो। इन पांच राज्यों के चुनावों ने भारतीय राजनीति का नया यथार्थ सामने रखा है। नतीजों से स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक किला स्थायी नहीं। मतदाता अब अधिक सजग और निर्णायक है और चुनाव अब केवल भावनात्मक मुद्दों से नहीं जीते जाते। 2027 के चुनाव इस यथार्थ की पुष्टि करेंगे। यह तय करेंगे कि हालिया बदलाव केवल अपवाद हैं या एक स्थायी प्रवृत्ति का हिस्सा। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि वह हर चुनाव के साथ खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। और यही प्रक्रिया 2027 में एक बार फिर देखने को मिलेगी, जहां मतदाता न केवल सरकार चुनेगा, बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करेगा।

प्रेरणा

भेंट का भाव और अहंकार का अदृश्य बोझ

मनुष्य के जीवन में देने और पाने की प्रक्रिया केवल व्यवहारिक नहीं, बल्कि गहराई से आध्यात्मिक भी होती है। हम जब किसी को कुछ देते हैं, तो वह केवल वस्तु का हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की भावना, संस्कार और दृष्टिकोण का भी प्रदर्शन होता है। इसी संदर्भ में एक प्रसंग हमें यह समझाता है कि भेंट का असली मूल्य उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी नीयत में होता है।

एक दिन कुछ लोग, जो नियमित रूप से एक फकीर के पास बैठकर उनके विचारों और किस्सों का आनंद लिया करते थे, उनके पास पहुंचे और विनम्रता से बोले कि आप हमें हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं—ज्ञान, अनुभव और जीवन की समझ। अब हमारी भी इच्छा है कि हम अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको कुछ भेंट दें। फकीर ने मुस्कुराते हुए उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा कि यदि ऐसा है तो कल ही अपनी-अपनी भेंट लेकर आ जाना।

अगले दिन सभी लोग पूरे उत्साह के साथ आए। हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ था—किसी के पास मिठाई, किसी के पास कपड़े, किसी के पास महंगी वस्तुएं। सभी के मन में एक संतोष भी था और एक हल्की सी अपेक्षा भी कि उनकी भेंट को पहचाना जाएगा, सराहा जाएगा। जब फकीर ने उन सभी भेंटों को देखा, तो वे हल्के से मुस्कुराए और बोले कि तुम सबने भी वही गलती कर दी, जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा आ गई। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्होंने क्या गलती की है।

फकीर ने एक पुरानी घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एक बार एक सूफी संत के पास भी इसी प्रकार लोग भेंट लेकर पहुंचे थे। वहां भी कुछ लोगों ने अपनी-अपनी सौगातों पर अपना नाम लिख दिया था, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसने कौन सी भेंट दी है और उसकी कीमत क्या है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने अपनी भेंट पर कोई नाम नहीं लिखा था। जब सूफी संत ने सभी भेंटों को देखा, तो उन्होंने केवल बिना नाम वाली भेंटों को स्वीकार किया और जिन पर नाम लिखा था, उन्हें वापस कर दिया।

जब लोगों ने इसका कारण पूछा, तो सूफी संत ने शांत भाव से उत्तर दिया कि भेंट देना एक श्रेष्ठ आदत है, लेकिन जब हम अपने नाम के साथ भेंट देते हैं, तो हम अनजाने में सामने वाले पर एक प्रकार का बोझ डाल देते हैं। वह व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसे उस भेंट के बदले में क्या करना चाहिए, कैसे उस उपकार को चुकाना चाहिए, या देने वाले के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रकार वह भेंट, जो स्नेह और सरलता का प्रतीक होनी चाहिए थी, एक मानसिक दबाव बन जाती है।

यह सुनकर फकीर के सामने बैठे लोगों को अपनी गलती का अहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने भेंट को केवल एक औपचारिकता या प्रदर्शन का माध्यम बना दिया था। उनके भीतर कहीं न कहीं यह इच्छा थी कि उनकी पहचान हो, उनका नाम लिया जाए, और उन्हें विशेष माना जाए। यही वह सूक्ष्म अहंकार है, जो हमारे अच्छे कार्यों को भी हल्का कर देता है।

इस प्रसंग के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि देने का भाव जितना सरल और निःस्वार्थ होगा, उतना ही वह पवित्र और प्रभावशाली होगा। यदि देने के पीछे कोई अपेक्षा जुड़ी हो—चाहे वह प्रशंसा की हो, पहचान की हो, या प्रतिदान की—तो वह भावना धीरे-धीरे अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाती है। फिर वह एक लेन-देन जैसा बन जाता है, जिसमें आत्मीयता की जगह गणना और तुलना आ जाती है।

आज के समय में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। उपहार देना कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। लोग इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि किसने कितना महंगा उपहार दिया, किसका उपहार सबसे आकर्षक था, और किसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस प्रतिस्पर्धा में उपहार देने का मूल उद्देश्य कहीं खो जाता है। वह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, जिसमें भावनाओं की गहराई नहीं होती। जब हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तो हमारे भीतर एक अलग प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। यह आनंद बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। इसमें न कोई तुलना होती है, न कोई अहंकार। यह एक शांत और संतुलित संतोष देता है, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। वहीं, जब हम अपेक्षा के साथ देते हैं, तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म तनाव बना रहता है—यह देखने का कि सामने वाला हमारी भेंट को कैसे स्वीकार करता है, क्या वह हमारी सराहना करता है, या क्या वह बदले में कुछ करता है। यही तनाव उस भेंट को बोझ में बदल देता है।

जीवन की सच्चाई यही है कि सच्चे संबंध वहीं बनते हैं, जहां लेन-देन की भावना नहीं होती। जहां देने और पाने का हिसाब नहीं रखा जाता, बल्कि केवल प्रेम और सम्मान का आदान-प्रदान होता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारे संबंध अधिक सहज, मजबूत और दीर्घकालिक बनते हैं।

इस कथा का सार यही है कि भेंट का मूल्य उसकी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होता है। यदि उस भावना में अहंकार या अपेक्षा की मिलावट हो जाए, तो वह भेंट अपना असली अर्थ खो देती है। लेकिन यदि वह पूर्णतः निःस्वार्थ और सरल हो, तो वह छोटी से छोटी वस्तु भी अत्यंत मूल्यवान बन जाती है। अंततः, हमें यह समझना होगा कि देने का आनंद तभी पूर्ण होता है, जब हम स्वयं को उस प्रक्रिया से अलग कर दें। जब हम अपने नाम, अपनी पहचान और अपनी अपेक्षाओं को पीछे छोड़कर केवल देने के भाव में लीन हो जाते हैं, तभी हम वास्तव में उस अनुभव को जी पाते हैं, जिसे सच्चा दान कहा जाता है। यही वह दृष्टिकोण है, जो हमारे जीवन को हल्का, सरल और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है।

बंगाल विजयः संघ की जमीनी साधना शांति से शक्ति तक

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ऐतिहासिक, अद्भुत, अविस्मरणीय एवं करिश्माई जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ) की बहुत बड़ी भूमिका रही है। निश्चिततौर पर इस शानदार जीत के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह मुख्य भूमिका में हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूत चुनौती के सामने भाजपा की जीत के लिए संघ लंबे समय से मेहनत कर रही थी और उसकी वह मेहनत ही जीत का सशक्त माध्यम बनी है। पश्चिम बंगाल में लगातार चल रही हिन्दू विरोधी गतिविधियों एवं मुसलमानों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए संघ ने इस चुनाव के मद्देनजर बहुत पहले से ही कमर कस ली थी, संघ ने पश्चिम बंगाल में 1.75 लाख से अधिक छोटी-बड़ी बैठकें आयोजित कीं। पिछले 15 सालों में संघ ने पश्चिम बंगाल में तेजी से विस्तार किया है और एक मजबूत 'हिंदू वोट बैंक' तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों में संघ की शाखाओं की संख्या 900 से बढ़कर 5,000 तक पहुंच गई है। संघ के स्वयंसेवकों ने पश्चिम बंगाल में घर-घर जाकर 'बंग बचाओ' इस थीम पर 'मतदाता जागरूकता अभियान' चलाया। संघ की माइक्रो प्लानिंग ने बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक बढ़त दिलाई और सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनी। पश्चिम बंगाल चुनाव भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक 'मील का पत्थर' और ऐतिहासिक सफलता साबित हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल बड़े मंचों, विशाल रैलियों और जोरदार नारों से तय नहीं होती। कई बार असली लड़ाई उन स्तरों पर लड़ी जाती है, जहां न कैमरे पहुंचते हैं और न ही जमीनी प्रयास सुर्खियां बनती हैं। इस बार के चुनाव में एक ऐसी ही खामोश रणनीति कारगर साबित हुई है। जहां एक ओर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का आक्रामक चुनाव प्रचार केंद्र में रहा, वहीं दूसरी ओर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपेक्षाकृत शांत रहकर 'निःशब्द विप्लव' या 'मूक क्रांति' को अंजाम देते हुए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया। बंगाल की अस्मिता, विकास और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को आधार बनाकर जनजागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान महिला, युवा, प्रबुद्ध वर्ग, किसान, श्रमिक और अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों तक अलग-अलग तरीकों से पहुंचने की कोशिश की गई।

निश्चिततौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति ने वर्ष 2026 में जो ऐतिहासिक करवट ली, वह केवल सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत भी है। लंबे समय तक वामपंथी प्रभाव और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार जनमत ने जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में निर्णायक रूप से झुकाव दिखाया, उसने स्थापित राजनीतिक धारणाओं को चुनौती दी है। इस परिवर्तन के मूल में जो शक्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी रही है तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने एक अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। यह विजय केवल चुनावी रणनीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे संगठनात्मक परिश्रम, वैचारिक विस्तार और समाज के भीतर गहराई तक किए गए संवाद का परिणाम है। पश्चिम बंगाल में संघ का विस्तार किसी तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक सामाजिक दृष्टि का हिस्सा था। पिछले डेढ़ दशक में संघ ने प्रांत में जिस प्रकार अपनी शाखाओं का विस्तार किया और समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई, उसने एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। यह कार्य किसी प्रचार की तरह नहीं, बल्कि एक शांत सामाजिक प्रक्रिया एवं क्रांति की तरह हुआ, जिसने धीरे-धीरे जनमानस को प्रभावित किया। यही कारण है कि जब चुनाव का समय आया, तो एक पहले से तैयार मानसिकता भाजपा के पक्ष में खड़ी दिखाई दी।

इस पूरे परिदृश्य में सरसंघचालक मोहन भागवत की रणनीतिक दृष्टि को भी विशेष रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। उन्होंने बंगाल को केवल एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक भूमि के रूप में देखा, भारत की अस्मिता के रूप में देखा। जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं हैं। संघ के प्रयासों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने बंगाल की सांस्कृतिक चेतना को समझने और उससे जुड़ने का प्रयास किया। दुर्गा पूजा, काली पूजा और रामनवमी जैसे पर्वों को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे एक व्यापक सामाजिक जुड़ाव स्थापित हुआ। इस प्रक्रिया में हिंदुत्व को किसी बाहरी विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा के एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया। लंबे समय तक यह धारणा बनी रही कि बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व परस्पर विरोधी हैं, लेकिन इस चुनाव में यह धारणा काफी हद तक टूटती हुई दिखाई दी। "जय श्री राम" के साथ "जय मां काली" और "जय मां दुर्गा" जैसे नारों का समन्वय केवल राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश था, जिसने यह स्थापित किया कि क्षेत्रीय पहचान और व्यापक सांस्कृतिक विचारधारा के बीच कोई टकराव नहीं है। इस समन्वय ने मतदाताओं के भीतर एक नई प्रकार की आत्मजागरूकता उत्पन्न की, जहां वे केवल विकास या योजनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव के आधार पर भी निर्णय लेने लगे।

चुनाव के दौरान जिस प्रकार से 'अस्तित्व' एवं 'अस्मिता' का विमर्श उभरा, उसने इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी। संघ और भाजपा ने इसे केवल एक चुनावी मुकाबले के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष के रूप में स्थापित किया, जिसमें पहचान और सम्मान के प्रश्न प्रमुख हो गए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर लगाए गए तुष्टिकरण के आरोपों ने इस विमर्श को और तीव्र किया, जिससे मतदाताओं के बीच एक स्पष्ट ध्रुवीकरण देखने को मिला।

अभियान

अमरत्व की गूंजः बाबा बर्फानी और हिमालय की रहस्यमयी तपोभूमि

जब भी मन में भगवान शिव की अनंत, निर्विकार और रहस्यमयी छवि उभरती है, तो हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा का स्मरण स्वतः हो जाता है। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, तप, त्याग और आत्मिक जागरण का अद्भुत संगम है। बाबा बर्फानी के दर्शन की लालसा हर उस श्रद्धालु के हृदय में होती है, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहता है। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है—जहां हर कदम एक परीक्षा है और हर सांस एक साधना।

हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह पवित्र गुफा केवल बर्फ और पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य क्षण की साक्षी मानी जाती है, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। यही कारण है कि इसे "अमरनाथ" कहा जाता है—अमरता का नाथ, अमर ज्ञान का केंद्र। कहा जाता है कि इस गुफा में जो हिमलिंग बनता है, वह स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है, जो हर वर्ष सावन के पवित्र महीने में अपने पूर्ण आकार में प्रकट होता है और फिर धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है। यह अपने आप में एक चमत्कार है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है, और यही इसकी रहस्यमयता को और गहरा बनाता है।

इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पहुंचना आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी रास्तों, बर्फीली हवाओं और कम ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार रास्ते इतने संकरे होते हैं कि एक गलत कदम खतरनाक साबित हो सकता है। तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, और शरीर की सीमाएं बार-बार परखी जाती हैं। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद, हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, कमजोरी और अहंकार को परास्त करने की प्रक्रिया भी है।

अमरनाथ यात्रा का महत्व केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी प्रदान करती है। जब एक व्यक्ति इतने कठिन मार्ग को पार करता है, तो उसके भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह समझता है कि यदि वह इस यात्रा को पूरा कर सकता है, तो जीवन की अन्य कठिनाइयों का सामना भी कर सकता है। यह यात्रा व्यक्ति को धैर्य, संयम और विश्वास का वास्तविक अर्थ सिखाती है।

पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का निश्चय किया, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस रहस्य को कोई और न सुन सके। उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, नागों को शेषनाग झील के पास, और अपने गणों को पंचतरणी में त्याग दिया। यहां तक कि उन्होंने अपने गले से विष को भी अलग कर दिया, ताकि कथा के दौरान कोई विघ्न न आए। यह सब त्याग इस बात का प्रतीक है कि जब तक हम अपने आस-पास के मोह और बंधनों को नहीं छोड़ते, तब तक हम जीवन के गहरे सत्य को नहीं समझ सकते।

लेकिन कथा के अनुसार, एक कबूतर का जोड़ा इस गुफा में मौजूद था, जिसने यह अमर कथा सुन ली। मान्यता है कि वही कबूतर आज भी इस गुफा के आसपास दिखाई देते हैं और उन्हें अमर माना जाता है। यह कथा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि ज्ञान और सत्य का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह साधारण को भी असाधारण बना देता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु केवल भगवान शिव के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि वे एक सामूहिक भक्ति और सेवा की भावना का भी अनुभव करते हैं। रास्ते में जगह-जगह लंगर लगे होते हैं, जहां निःस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। कोई भूखा नहीं रहता, कोई अकेला नहीं होता। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और सहयोग में भी होती है।

इस यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस यात्रा को पूरा करता है, उसके जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। यह केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जिसे लाखों श्रद्धालु हर साल महसूस करते हैं। जब व्यक्ति बाबा बर्फानी के सामने खड़ा होता है, तो उसके मन में चल रही सारी उलझनें, दुख और चिंताएं स्वतः शांत हो जाती हैं। वह एक ऐसी शांति का अनुभव करता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है।

अमरनाथ गुफा का रहस्य केवल इसके धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और दिव्यता के अद्भुत संगम का उदाहरण भी है। बर्फ से बना शिवलिंग हर साल अपने आप बनता है और चंद्रमा के आकार के अनुसार घटता-बढ़ता है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, तो कुछ इसे दिव्य चमत्कार के रूप में देखते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है, जिसमें उन्हें अपनी आस्था और विश्वास का आधार मिलता है।

इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को विनम्र बनाती है। जब वह विशाल पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बीच खुद को छोटा महसूस करता है, तो उसका अहंकार स्वतः समाप्त होने लगता है। वह समझता है कि प्रकृति के सामने उसकी शक्ति सीमित है, और यही समझ उसे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनाती है।

अंततः, बाबा बर्फानी के दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर के भय, अहंकार और मोह को त्याग देते हैं, तभी हम उस परम सत्य को समझ पाते हैं, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। अमरनाथ की यह पवित्र गुफा आज भी उसी अमर रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है, जो हजारों साल पहले प्रकट हुआ था। हर साल लाखों श्रद्धालु इस रहस्य को महसूस करने के लिए वहां पहुंचते हैं, और अपने साथ एक नई ऊर्जा, नई आस्था और एक नई दृष्टि लेकर लौटते हैं। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है—यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है, जो जीवन को एक नई दिशा देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

खुले पानी के टैंक ने निगल ली दो मासूम जिंदगियां जयपुर में दर्दनाक हादसे से दहला पूरा इलाका

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार रात हुआ एक दर्दनाक हादसा पूरे शहर को झकझोर गया। शिप्रापथ थाना क्षेत्र की जगन्नाथपुरी सेकंड कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में बने खुले पानी के टैंक में गिरने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना ने न केवल दो गरीब परिवारों की दुनिया उजाड़ दी, बल्कि निर्माण स्थलों पर बरती जा रही लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की आंखें नम हैं।

मृतक बच्चियों की पहचान 5 वर्षीय राधिका और 6 वर्षीय गौसिया के रूप में हुई है। दोनों बच्चियां शाम के समय अपने घर के पास खेल रही थीं। उन्हें क्या पता था कि खेल-खेल में वे मौत के इतने करीब पहुंच चुकी हैं। जिस निर्माणाधीन मकान के पास वे खेल रही थीं, वहां करीब आठ फीट गहरा पानी का टैंक बनाया गया था, जिसे खुला छोड़ दिया गया था। यही लापरवाही दोनों मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, मकान का निर्माण कार्य पिछले लगभग दस दिनों से बंद पड़ा था। निर्माणाधीन भवन के मालिक ने वहां पानी संग्रह के लिए गहरा हौद बनवाया था, लेकिन उसे ढंकने या उसके आसपास सुरक्षा इंतजाम करने की कोई कोशिश नहीं की गई। टैंक पानी से लबालब भरा हुआ था और उसके आसपास कोई चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा घेराबंदी भी नहीं थी। शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों बच्चियां खेलते-खेलते उसी खुले टैंक के पास पहुंचीं और अचानक उसमें गिर गईं।

घटना के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। पानी के टैंक के किनारे पड़ी बच्चियों की छोटी-छोटी चप्पलें उस भयावह हादसे की मूक गवाह बन गईं। देर रात तक परिजन अपनी बच्चियों को आसपास तलाशते रहे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटियां उसी खुले टैंक में जिंदगी हार चुकी हैं।

दोनों बच्चियों के परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर बताए जा रहे हैं। राधिका का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि गौसिया का परिवार बिहार से जयपुर आकर मजदूरी कर रहा था। दोनों परिवार किराए के छोटे मकानों में रहते हैं और रोज कमाने-खाने वाली जिंदगी जी रहे थे।

राधिका के पिता दिव्यांग हैं और ट्राईसाइकिल पर घूम-घूमकर मोबाइल कवर बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। दूसरी ओर गौसिया के पिता पेंटर का काम करते हैं। परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटियां ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थीं। हादसे के बाद दोनों परिवारों की हालत बेहद खराब है। रोते-बिलखते परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा है।

घटना से कुछ समय पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने पूरे हादसे को और अधिक दर्दनाक बना दिया। फुटेज में दोनों मासूम बच्चियां हंसते-खेलते निर्माणाधीन मकान के आसपास घूमती दिखाई दे रही हैं। वे पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रही थीं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह फुटेज देखने के बाद स्थानीय लोगों में भी गहरा आक्रोश है।

घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान पुलिस की शिप्रापथ थाना टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चियों के शव पानी के टैंक से बाहर निकलवाए। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। निर्माणाधीन मकान के मालिक और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में कई निर्माणाधीन मकानों पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जाती है। खुले गड्ढे, पानी से भरे टैंक और असुरक्षित निर्माण सामग्री बच्चों और राहगीरों के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए गए होते, तो शायद दो मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं होता। अक्सर निर्माणाधीन भवनों में खुले गड्ढे, बिना ढंके टैंक और असुरक्षित ढांचे हादसों को न्योता देते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई केवल घटना के बाद ही दिखाई देती है।

सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए और निर्माण स्थलों के लिए स्पष्ट सुरक्षा दिशा-निर्देश लागू किए जाएं। उनका कहना है कि मासूम बच्चों की जान किसी की लापरवाही की कीमत नहीं बननी चाहिए।

पूरे इलाके में इस घटना के बाद शोक और गुस्से का माहौल है। हर कोई यही कह रहा है कि यदि थोड़ी सी सावधानी बरती गई होती, तो दो परिवारों की खुशियां इस तरह उजड़ती नहीं। मासूम बच्चियों की मौत ने यह साफ कर दिया है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा की अनदेखी केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि कई बार जानलेवा साबित हो सकती है।

धौलपुर में रिश्तों और भरोसे को शर्मसार करने वाली वारदात, युवती से दुष्कर्म के आरोप में दो युवक फरार

राजस्थान के धौलपुर जिले से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक 19 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। आरोप है कि दो युवकों ने योजनाबद्ध तरीके से युवती को बहला-फुसलाकर सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद से क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि गांव का ही एक युवक अपने दूसरे साथी के साथ युवती को अपने झांसे में लेकर गया था। दोनों आरोपी पहले से योजना बनाकर आए थे। आरोप है कि युवती को गांव के एक सूने मकान में ले जाया गया, जहां एक युवक बाहर निगरानी करता रहा जबकि दूसरा अंदर युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा।

परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने पूरी वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। युवती को भरोसे में लेकर घर से बाहर बुलाया गया और फिर उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहां पहले से कोई मौजूद नहीं था। पुलिस मान रही है कि घटना पूर्व नियोजित हो सकती है और दोनों आरोपियों ने अपनी भूमिकाएं पहले से तय कर रखी थीं।

घटना का खुलासा तब हुआ जब युवती के भाई को इस संबंध में जानकारी मिली। बहन की तलाश करते हुए वह बताए गए स्थान पर पहुंचा, जहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। आरोप है कि जब उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की और आरोपियों का विरोध किया, तो दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों का कहना है कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया, उन्हीं ने इस विश्वास को तोड़ते हुए परिवार की इज्जत और बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। गांव में भी इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। धौलपुर ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने वहां से कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

घटना के बाद इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांवों में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सामाजिक दबाव और डर के कारण कई मामले सामने ही नहीं आ पाते।

महिला अधिकारों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाएं केवल अपराध नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती संवेदनहीनता और महिलाओं के प्रति विकृत मानसिकता का संकेत हैं। उनका कहना है कि केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और कठोर सजा सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय पैदा हो।

पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और हर संभव कानूनी सहायता देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मामले की जांच निष्पक्ष और तेजी से की जाएगी। पुलिस का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवतियों को झांसे में लेकर अपराध करने की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवार और समाज दोनों स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लड़कियां ऐसे जाल में फंसने से बच सकें।

धौलपुर की यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली दर्दनाक सच्चाई भी है। जिस भरोसे और पहचान का सहारा लेकर युवती को फंसाया गया, वही इस अपराध का सबसे भयावह पहलू बन गया। अब पूरे क्षेत्र की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होकर कानून के कठघरे तक पहुंचेंगे।

जैसलमेर में सुनसान इलाके में मिला संदिग्ध मोर्टार बम ग्रामीणों में दहशत, सेना के बम निरोधक दस्ते का इंतजार

राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एक बार फिर संदिग्ध विस्फोटक मिलने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। पश्चिमी सरहद से लगे इलाके में स्थित फुलिया गांव के पास एक पुराना मोर्टार बम मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सुनसान इलाके में पड़े इस संदिग्ध बम को देखकर ग्रामीणों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

घटना जैसलमेर जिले के म्याजलार थाना क्षेत्र की है, जहां गांव से कुछ दूरी पर खुले इलाके में ग्रामीणों की नजर एक संदिग्ध धातु जैसी वस्तु पर पड़ी। नजदीक जाकर देखने पर आशंका हुई कि यह कोई मोर्टार बम हो सकता है। इसके बाद लोगों ने बिना देर किए पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस तरह की किसी भी वस्तु को लेकर प्रशासन अत्यधिक सतर्क रहता है।

सूचना मिलते ही म्याजलार थाना प्रभारी सज्जन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबसे पहले आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया गया। पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लोगों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगा दी और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बरामद मोर्टार बम काफी पुराना हो सकता है। अधिकारियों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां समय-समय पर सेना के युद्धाभ्यास होते रहते हैं। संभावना जताई जा रही है कि किसी पुराने सैन्य अभ्यास के दौरान यह मोर्टार बम वहां रह गया होगा, जो उस समय विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि यह निष्क्रिय है या अब भी सक्रिय अवस्था में है, इसका पता सेना के विशेषज्ञों की जांच के बाद ही चल सकेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने

तत्काल भारतीय सेना को सूचना भेज दी है। सेना के बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है, जो पहुंचकर मोर्टार बम की तकनीकी जांच करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करेगा। थाना प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया कि फुलिया गांव से करीब दो किलोमीटर दूर यह संदिग्ध बम मिला था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मोर्टार के आसपास रेत के कट्टे लगाकर उसे ढंक दिया, ताकि किसी संभावित विस्फोट की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और आम लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, इलाके में पहले भी कई बार पुराने बम, ग्रेनेड या अन्य विस्फोटक सामग्री मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने और लंबे समय से सैन्य गतिविधियां चलने के कारण यहां ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। हालांकि हर बार प्रशासन और सेना की तत्परता से स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाता है।

स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सुनसान इलाकों में इस तरह की वस्तुएं लंबे समय तक पड़ी रह सकती हैं और अनजाने में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने मोर्टार या विस्फोटक कई बार वर्षों तक जमीन में दबे रहने के बाद भी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूना या उसके पास जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रकार की वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें और उससे दूरी बनाए रखें।

जैसलमेर और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की नियमित गतिविधियां होती रहती हैं। यहां युद्धाभ्यास, फायरिंग ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के अवशेष कई बार खुले इलाकों में मिल जाते हैं। हालांकि सेना और प्रशासन समय-समय पर ऐसे इलाकों की जांच करते रहते हैं, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र के विशाल विस्तार के कारण कुछ वस्तुएं लंबे समय तक नजर से बच जाती हैं।

इस घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सेना के बम निरोधक दस्ते के पहुंचने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मोर्टार बम कितना खतरनाक था और उसे किस तरीके से निष्क्रिय किया जाएगा। फिलहाल फुलिया गांव और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है ताकि कोई व्यक्ति गलती से भी घटनास्थल के करीब न पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

जैसलमेर में सामने आई यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता कितनी जरूरी है। पुराने सैन्य उपकरण और विस्फोटक वर्षों बाद भी खतरा बन सकते हैं, इसलिए प्रशासन और स्थानीय लोगों दोनों की सजगता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डिंडोली के दीप दर्शन विद्या संकुल ने रचा सफलता का नया इतिहास, 10वीं बोर्ड में शानदार परिणाम से पूरे क्षेत्र में बढ़ाया गौरव

सूरत के शिक्षा जगत में इस वर्ष एक बार फिर दीप दर्शन विद्या संकुल का नाम प्रमुखता से उभरकर सामने आया है। डिंडोली क्षेत्र स्थित इस विद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए हैं, बल्कि पूरे डिंडोली-गोडादरा क्षेत्र में अपनी मजबूत शैक्षणिक पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है। विद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धियों ने अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे शिक्षा जगत को गौरवान्वित कर दिया है।

इस वर्ष घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों में विद्यालय के 77 विद्यार्थियों ने A1 ग्रेड प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जबकि 88 विद्यार्थियों ने A2 ग्रेड प्राप्त किया। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का उच्च ग्रेड हासिल करना इस बात का प्रमाण माना जा रहा है कि विद्यालय लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करा रहा है।

विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही कि कुल 42 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। विज्ञान विषय में 25 विद्यार्थियों ने पूर्ण अंक हासिल कर विद्यालय की विज्ञान शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को साबित किया। इसके अलावा संस्कृत में 9, सामाजिक विज्ञान में 7 और गणित में 1 विद्यार्थी ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इतने बड़े स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण अंक हासिल करना विद्यालय की अकादमिक मजबूती का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

इस वर्ष विद्यालय में सर्वोच्च स्थान पटेल आर्या कीर्तिकुमार ने प्राप्त किया। उन्होंने 600 में से 584 अंक हासिल कर 99.92 पीआर के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे विद्यालय को गौरवान्वित कर दिया। शिक्षकों के अनुसार आर्या ने पूरे वर्ष अत्यंत अनुशासन और समर्पण के साथ अध्ययन किया, जिसका

परिणाम इस शानदार सफलता के रूप में सामने आया।

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह सफलता केवल विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। विद्यालय ने छात्रों को केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्र-छात्राओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी साझा की, जबकि अभिभावकों ने भी विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कई विद्यार्थियों और अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय ने पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक सहयोग और सकारात्मक वातावरण देकर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर विद्यालय के संचालक दशरथभाई पटेल और तुषारभाई पटेल ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सफलता यह दर्शाती है कि यदि सही दिशा, अनुशासन और निरंतर प्रयास हो, तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

विद्यालय की प्रधानाचार्या आशाबेन पटेल ने भी विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि यह परिणाम विद्यालय की शैक्षणिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने शिक्षकों की टीम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने पूरे वर्ष विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया।

विद्यालय के अन्य शिक्षकों और प्रबंधन सदस्यों—प्रांशुसिंह राजपूत, कृतिबेन देसाई, रसीलाबेन पटेल और सपनाबेन जायसवाल—ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। विद्यालय द्वारा सफल छात्रों का सम्मान पुष्पगुच्छ भेंट कर और मुँह मीठा कराकर किया गया। इस दौरान छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बेहतर परिणाम किसी भी विद्यालय की शिक्षण गुणवत्ता, अनुशासन और प्रबंधन क्षमता को दर्शाते हैं। दीप दर्शन विद्या संकुल ने पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, वह सूरत के उभरते शिक्षा केंद्रों में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

डिंडोली और गोडादरा जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस प्रकार के परिणाम न केवल विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य छात्रों और अभिभावकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं।

विद्यालय प्रबंधन ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल लर्निंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी केवल बोर्ड परीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो सकें।

कुल मिलाकर, दीप दर्शन विद्या संकुल का यह परिणाम केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस शैक्षणिक संस्कृति और मेहनत का प्रतीक है, जिसने विद्यालय को पूरे क्षेत्र में उत्कृष्टता का उदाहरण बना दिया है। विद्यार्थियों की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समर्पण, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के साथ हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

क्रूड ऑयल वायदा में 1139 रुपये की भारी गिरावटः सोना वायदा में 2788 रुपये और चांदी वायदा में 9990 रुपये का ऊछाल

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 260039.79 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 43951.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 216088.04 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मई वायदा 36834 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5470.36 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 26780.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 152000 रुपये के भाव पर खूलकर, 152889 रुपये के दिन के उच्च और 151653 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 149753 रुपये के पिछले बंद के सामने 2788 रुपये या 1.86 फीसदी की बढ़त के साथ 152541 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 1834 रुपये या 1.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 122662 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 220 रुपये या 1.45 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15368 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 150699 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152830 रुपये और नीचे में 150699 रुपये पर पहुंचकर, 2728 रुपये या 1.82 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 150949 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153000 रुपये और नीचे में 150949 रुपये पर पहुंचकर, 150097 रुपये के पिछले बंद के सामने 2578 रुपये या 1.72 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 249316 रुपये के भाव पर खूलकर, 255409 रुपये के दिन के उच्च और 249316 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 244316 रुपये के पिछले बंद के सामने 9990 रुपये या 4.09 फीसदी की तेजी के संग 254306 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 9117 रुपये या 3.68 फीसदी की मजबूती के साथ 257170 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो

जून वायदा 9064 रुपये या 3.65 फीसदी की तेजी के संग 257173 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 4742.35 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 23.65 रुपये या 1.84 फीसदी बढ़कर 1311.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 1.9 रुपये या 0.55 फीसदी की तेजी के संग 347.55 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 6.3 रुपये या 1.68 फीसदी औंधकर 368.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 85 पैसे या 0.42 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 201 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 12036.73 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9610 रुपये के भाव पर खूलकर, 9644 रुपये के दिन के उच्च और 8380 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1139 रुपये या 11.74 फीसदी की गिरावट के साथ 8559 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 1142 रुपये या 11.77 फीसदी लुढ़ककर 8557 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 267 रुपये के भाव पर खूलकर, 267 रुपये के दिन के उच्च और 255.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 267 रुपये के पिछले बंद के सामने 10.2 रुपये या 3.82 फीसदी गिरकर 256.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 9.8 रुपये या 3.67 फीसदी औंधकर 257.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 43951.32 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 216088.04 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 26780.60 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36834 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 989.9 रुपये पर खूलकर, 70 पैसे या 0.07 फीसदी घटकर 986.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16314.15 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 10466.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3705.77 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 666.37 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 23.18 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 329.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 9848.16 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2155.33 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 0.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11012 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 63852 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26628 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 356346 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 56948 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7407 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22532 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 76389 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17665 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31444 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मई वायदा सत्र के आरंभ में 36539 पॉइंट पर खूलकर, 36834 के उच्च और 36539 के नीचले स्तर को छूकर, 813 पॉइंट बढ़कर 36834 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 286.9 रुपये की गिरावट के साथ 118.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.2 रुपये की गिरावट के साथ 6.95 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 771 रुपये की बढ़त के साथ 2035 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 279.5 रुपये की बढ़त के साथ 746.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 9.35 रुपये की बढ़त के साथ 15.84 रुपये हुआ। जस्ता मई 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.4 रुपये की बढ़त के साथ 4.19 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 205.6 रुपये की बढ़त के साथ 279.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.25 रुपये की बढ़त के साथ 13.45 रुपये हुआ।

सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 1310 रुपये की गिरावट के साथ 1996 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 696.5 रुपये की गिरावट के साथ 1109 रुपये हुआ। तांबा मई 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.05 रुपये की गिरावट के साथ 7.21 रुपये हुआ। जस्ता मई 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 45 पैसे के सुधार के साथ 2.9 रुपये हुआ।

जयपुर एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का बड़ा खुलासा, महिला यात्री से 22 करोड़ की कोकीन बरामद

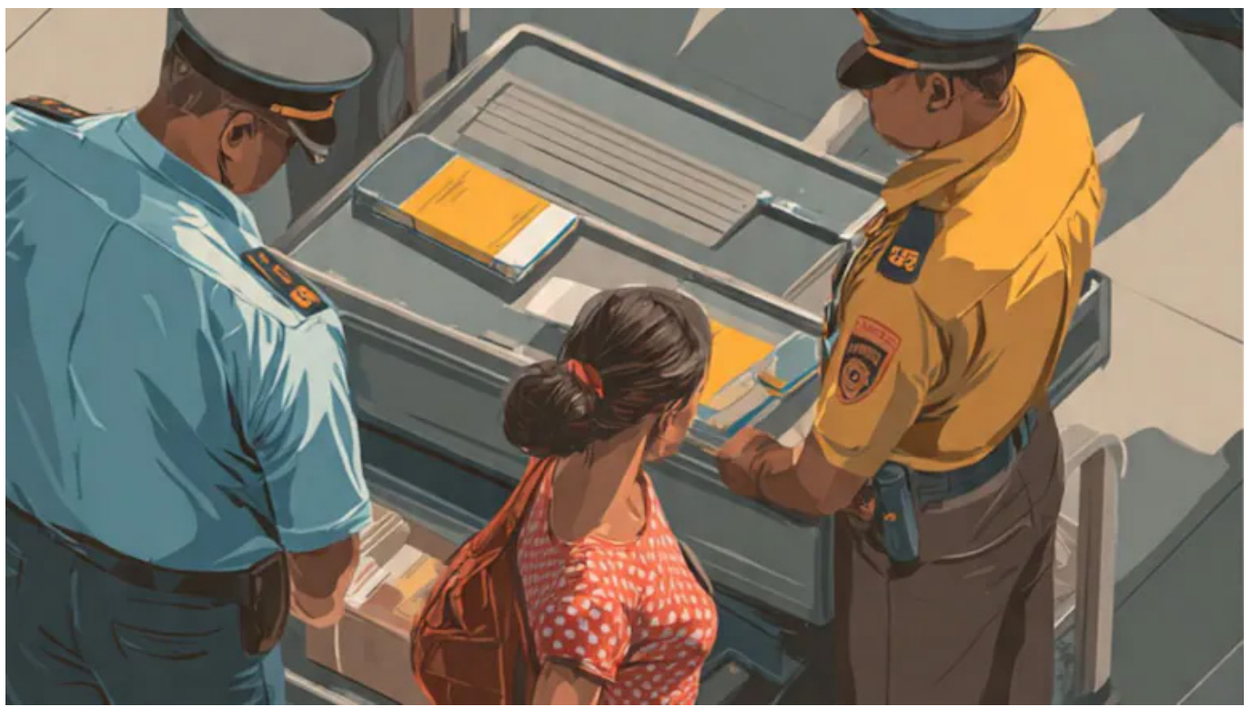

जयपुर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उस समय अचानक सुर्खियों में आ गया जब राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक महिला यात्री के पास से भारी मात्रा में कोकीन बरामद की। यह मामला केवल एक गिरफ्तारी या बरामदगी भर नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क की गहराई और उसकी भारत में बढ़ती सक्रियता की ओर इशारा करता है।

यह घटना 5 मई को सामने आई, जब बैंकॉक से जयपुर आने वाली फ्लाइट संख्या FD-130 पर DRI की खुफिया टीम ने विशेष निगरानी शुरू की। एजेंसियों को पहले से इनपुट मिला था कि इस उड़ान के जरिए नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप भारत लाई जा सकती है। इसी इनपुट के आधार पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और संदिग्ध यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। जांच के दौरान एक महिला यात्री को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। वह सामान्य यात्रियों की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसके सामान को लेकर एजेंसियों को संदेह हुआ। जब उसके ट्रॉली बैग की गहन तलाशी ली गई, तो उसमें से जो बरामद हुआ उसने सभी को चौंका दिया। बैग के भीतर छिपाकर रखी गई 4.556 किलोग्राम कोकीन मिली, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 22.78 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी ने यह साफ कर दिया कि यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क हो सकता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की खेपें आमतौर पर कई देशों के बीच नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाती हैं, जिसमें एयरपोर्ट, ट्रांजिट देश और अंतिम गंतव्य तक अलग-अलग लोग शामिल होते हैं।

महिला यात्री को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। प्रारंभिक जांच के बाद 6 मई को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद सतर्कता बरती ताकि किसी भी प्रकार की चूक या बाहरी हस्तक्षेप न हो।

इस घटना ने राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरपोर्ट जैसे अत्यधिक सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का पहुंच जाना यह दर्शाता है कि तस्करी नेटवर्क कितने आधुनिक और चालाक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

DRI अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के मामलों में अक्सर कैरियर (Carrier) का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें या तो पैसे का लालच दिया जाता है या फिर धोखे में रखकर इस काम में शामिल किया जाता है। कई मामलों में उन्हें यह भी नहीं बताया जाता कि वे किस तरह के अपराध में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि लोग जानबूझकर इस नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं।

इस केस में भी जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या महिला अकेले काम कर रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। उसके संपर्क, यात्रा इतिहास, बैंकॉक में उसके ठहराव और भारत में उसके संपर्कों की गहन जांच की जा रही है।

बैंकॉक को लेकर जांच एजेंसियों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यह शहर लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के ट्रांजिट हब के रूप में पहचाना जाता है। वहां से कई देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि यह खेप किसी बड़े एशियाई या अंतरमहाद्वीपीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है।

एयरपोर्ट पर इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सभी यात्रियों की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में तकनीकी निगरानी को और मजबूत किया जाएगा, ताकि ऐसे मामलों को शुरुआती चरण में ही रोका जा सके।

इस मामले ने यह भी उजागर किया है कि आधुनिक ड्रग्स तस्करी केवल सड़क या समुद्री मार्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब हवाई मार्ग इसका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ माध्यम बन चुका है। इसकी वजह यह है कि हवाई यात्रा तेज होती है और कई बार सामान की जांच में बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसका फायदा तस्कर उठाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े और युवा जनसंख्या वाले देश में ड्रग्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, और यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय माफिया यहां अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

इस घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि एयरपोर्ट सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाए। खासकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए स्कैनिंग तकनीक, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीयल टाइम मॉनिटरिंग को बढ़ाने की मांग उठ रही है।

जांच एजेंसियां अब इस बात की भी तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि इस खेप का अंतिम गंतव्य क्या था। क्या यह भारत में ही खपाई जानी थी या फिर इसे किसी अन्य देश में आगे भेजा जाना था। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसियों से भी संपर्क साधा जा रहा है।

इसके साथ ही यह भी जांच का विषय है कि क्या यह पहली बार था जब इस नेटवर्क ने भारत में इस तरह की खेप भेजी, या इससे पहले भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा है, तो यह मामला और भी गंभीर हो सकता है। कुल मिलाकर, जयपुर एयरपोर्ट पर हुई यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि ड्रग्स तस्करी का खतरा अब वैश्विक स्तर पर और अधिक संगठित और जटिल होता जा रहा है। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक है कि उन्हें अपनी रणनीतियों, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना होगा। यह मामला आने वाले समय में न केवल कानूनी जांच का हिस्सा रहेगा, बल्कि यह भारत की ड्रग्स विरोधी नीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

गुजरात में नर्सिंग सेक्टर को मिली नई पहचान, ऐतिहासिक भर्तियों और सुधारों पर स्वास्थ्य मंत्री का सम्मान

सूरत में नर्सिंग क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए बड़े कदमों के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नई ऊर्जा और विश्वास का माहौल दिखाई दे रहा है। नर्सिंग कैडर में बड़े स्तर पर हुई पारदर्शी भर्तियों और प्रशासनिक सुधारों के लिए नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुलभाई पंशेरिया से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात को गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सिंग समुदाय के बढ़ते महत्व और उसकी मजबूत होती भूमिका के रूप में देखा जा रहा है।

सूरत में आयोजित इस बैठक के दौरान नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात सरकार ने नर्सिंग क्षेत्र को केवल सहायक सेवा के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ के रूप में देखने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद नर्सिंग स्टाफ की भूमिका जिस तरह उभरकर सामने आई, उसने इस क्षेत्र के महत्व को और अधिक मजबूत किया।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रफुलभाई पंशेरिया ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा, संवेदनशीलता और मानवता का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि किसी भी आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता केवल तकनीक या अस्पतालों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मरीजों के प्रति मानवीय व्यवहार और सेवा भावना पर भी आधारित होती है। उनके अनुसार यदि नर्सिंग शिक्षा में व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी जोड़ा जाए, तो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और मानवीय बनाया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि एक नर्स मरीज के सबसे कठिन समय में उसके साथ खड़ी रहती है और कई बार उसकी मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा आधार बनती है। इसलिए नर्सिंग क्षेत्र को केवल रोजगार के रूप में नहीं, बल्कि समाज सेवा के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए।

बैठक के दौरान इकबाल कड़ीवाला ने गुजरात में नर्सिंग शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद राज्य के 500 से अधिक नर्सिंग प्रोफेशनल्स का चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, विशेष रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जैसे संस्थानों में हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गुजरात की नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और यहां के विद्यार्थियों की क्षमता का प्रमाण है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के इतिहास में पहली बार गुजरात लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक ही वर्ष में 50 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों, प्रिंसिपलों, स्पेशलिस्ट और प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। इसे नर्सिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। इसके अलावा पिछले एक वर्ष में 5000 से अधिक नर्सिंग स्टाफ की स्थायी भर्ती भी की जा चुकी है, जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को बड़ी मजबूती मिली है।

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि 150 से अधिक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद भी भरे गए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर नर्सिंग प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकेगा। उनका कहना था कि लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की जा रही थी और सरकार के हालिया कदमों से नर्सिंग समुदाय में सकारात्मक संदेश गया है।

बैठक के दौरान नर्सिंग स्टाफ से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने नर्सिंग कर्मचारियों के अलाउंस में वृद्धि, विद्यार्थियों के स्टाइपेंड को बढ़ाने, लंबित प्रमोशन मामलों के समाधान और उच्च वेतनमान जैसी मांगों को मंत्री के सामने रखा। एसोसिएशन का कहना था कि लगातार बढ़ते कार्यभार और जिम्मेदारियों को देखते हुए नर्सिंग कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि सरकार नर्सिंग क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से समझती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों और नर्सिंग प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

खुले पैसों का झंझट खत्म ! जीएसआरीटीसी बसों में 30 प्रतिशत आय अब डिजिटल पेमेंट से होता है

▸▸ राज्य में 8000 से अधिक बसों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा यूपीआई से ऑनलाइन बुकिंग, मोबाइल ऐप एवं करंट बुकिंग द्वारा डिजिटिल पेमेंट की व्यवस्था की गई है, यह पहल मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के व्यापक प्रयासों को सार्थक सिद्ध करती है

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बस सुविधा बढ़ाने तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, यात्रियों को अधिक सुविधा मिले तथा दैनिक यात्रियों की संख्या बढ़े; उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है

गांधीनगर : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) द्वारा डिजिटल पेमेंट पर बल दिया जा रहा है और यात्रियों के लिए पेमेंट की अनुकूल व्यवस्था की गई हैं। राज्य की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का जबर्दस्त से विस्तार हो रहा है। आँकड़े उसका प्रमाण देते हैं। हाल में निगम की दैनिक आय में लगभग 30 प्रतिशत आय कैशलेस माध्यमों से होती है।

अहमदाबाद निवासी मनीष घाँची ने हाल ही में जीएसआरटीसी की प्रीमियम बस में वडोदरा जाने के लिए यात्रा की थी। नकद या खुले पैसों की चिंता किए बगैर उन्होंने कंडक्टर द्वारा तुरंत ही जनरेट किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर टिकट किराए का पेमेंट किया।

"जीएसआरटीसी की यह पहल वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझ जैसे हजारों लोग नियमित रूप से केवल डिजिटल पेमेंट का ही उपयोग करते हैं। उनके लिए यह व्यवस्था अत्यंत सुविधाजनक है", मनीष घाँची ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम की प्रशंसा करते हुए कहा।

राज्यभर में अब हजारों यात्रियों को यात्रा के दौरान नकद रखने की जरूरत नहीं रहती है। जीएसआरटीसी अब यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल आधारित ऑनलाइन पेमेंट सहित अनेक डिजिटल विकल्पों द्वारा टिकट किराया भुगतान की सुविधा देता है। इतना ही नहीं; डिजिटल ट्रांजेक्शन के बढ़ते उपयोग से निगम की कार्यक्षमता तथा पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में 8000 से अधिक बसों में यात्रा करने वाले यात्री विभिन्न डिजिटल माध्यमों से पेमेंट कर सकते हैं। यह पहल मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के व्यापक प्रयासों को सार्थक सिद्ध करती है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बस सुविधा बढ़ाने तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया है। यात्रियों को अधिक सुविधा मिले तथा दैनिक यात्रियों की संख्या बढ़े; उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

"औसत 27 लाख यात्री निगम की बसों में यात्रा करते हैं और लगभग दैनिक 12 करोड़ रुपए की आय होती है। उसमें लगभग 30 प्रतिशत आय अब डिजिटल पेमेंट द्वारा होती है। दैनिक डिजिटल कलेक्शन पिछले एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ रुपए से बढ़कर हाल में 2 करोड़ रुपए हो गया है और लगातार बढ़ रहा है। हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं तथा यह पहल डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का हिस्सा है", उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा।

निगम द्वारा विद्यार्थियों के 'पास' के लिए भुगतान भी डिजिटल किया गया है, जिससे डिजिटल आय में वृद्धि हुई है।

आगामी समय में गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कैशलेश ट्रांजेक्शन का दायरा और बढ़ाने का आयोजन किया गया है।

"आगामी महीनों में हम डिजिटल पेमेंट का हिस्सा 60 से 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इसके लिए कॉमर्शियल सेवाओं तथा पैसेंजर पास सिस्टम में भी यह डिजिटल पेमेंट लाएंगे", निगम के उच्चाधिकारी ने कहा। उल्लेखनीय है कि जीएसआरटीसी में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन में लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई का है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि समग्र गुजरात में यूपीआई का दायरा कितना बढ़ा है।

महेसाणा से पहली मसालों से लदी ट्रेन असम के लिए रवाना अहमदाबाद मंडल ने माल ढुलाई में स्थापित किए नए कीर्तिमान

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल माल परिवहन एवं राजस्व अर्जन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल करते हुए भारतीय रेलवे के फ्रेट ऑपरेशन को नई दिशा दे रहा है। मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में मंडल द्वारा कई नवाचारपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ देशव्यापी आपूर्ति श्रृंखला भी सुदृढ़ हो रही है।

इसी क्रम में 06 मई 2026 को अहमदाबाद मंडल के महेसाणा स्टेशन से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के रंगिया मंडल स्थित अजारा स्टेशन (असम) के लिए 4200 क्विंटल जीरा से लदी पहली 'डीम्ड वीपी रेक' सफलतापूर्वक रवाना की गई। यह अहमदाबाद मंडल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार इस सेक्टर में मसालों की संगठित रेल ढुलाई की गई है। इस परिवहन से रेलवे को लगभग 25 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पहल गुजरात के मसाला उद्योग को पूर्वोत्तर भारत के बाजारों से सीधे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, यह रेल परिवहन को सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में और अधिक मजबूत करेगी। इससे व्यापारियों एवं निर्यातकों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी और भविष्य में इस तरह के फ्रेट मूवमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी।

"कच्छ से कश्मीर" तक मजबूत लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी

अहमदाबाद मंडल ने हाल ही में एक और उपलब्धि दर्ज करते हुए गांधीधाम क्षेत्र के भीमासर स्टेशन से जम्मू-कश्मीर के बाड़ी ब्राह्मण (BBMN) और अनंतनाग तक खाद्य तेल की सफल माल ढुलाई की।

इस विशेष फ्रेट मूवमेंट में:

11 BCN वैगन बाड़ी ब्राह्मण के लिए

09 BCN वैगन अनंतनाग के लिए भेजे गए

इससे रेलवे को 17 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।

"कच्छ से कश्मीर" तक खाद्य तेल की यह निर्बाध आपूर्ति भारतीय रेलवे की व्यापक पहुंच और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार और उद्योग को मिल रही नई गति अहमदाबाद मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) द्वारा उद्योगों एवं व्यापारिक संस्थानों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित और कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक समाधान प्रदान किए जा रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूपः

नए कमोडिटी ट्रैफिक का विस्तार हो रहा है

व्यापारिक समुदाय का रेलवे पर विश्वास बढ़ रहा है

सड़क परिवहन पर दबाव कम हो रहा है

दलित छात्रों का संघर्ष: शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव, भय और असमानता

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज भी भारत में शैक्षणिक रूप से सफल दलित छात्रों को शिक्षण संस्थानों में भेदभाव, बहिष्कार और समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, व्यवस्थागत बाधाएं और छात्रवृत्तियों में कटौती उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। क्या कभी कैंपस में उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा? एक दलित पिता की पीड़ाः "मेरे बड़े बेटे ने इस साल सीबीएसई की 10वीं कक्षा में 93% अंक प्राप्त किए हैं । खुश होने के बजाय, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे उसे कॉलेज भेजने से डर लग रहा है।" दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मेरे बेटे को उसके 93% अंकों पर बधाई देना शुरू कर दिया है। मेरा छोटा बेटा भी एक होशियार छात्र है।

हमारे देश में, योग्यता और पद का निर्धारण केवल निर्धारित मानदंडों के अनुसार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। उनके सामने अध्ययन के लिए प्रवेश पत्र लाए गए हैं। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। क्योंकि इस प्रवेश पत्र को देखते ही स्वाभाविक रूप से मुझे भय लगने लगता है। मुझे कॉलेज से, कक्षा से, छात्रावास के गलियारे से डर लगता है। मुझे उस शिक्षक से डर लगता है जो मेरे बेटे से उसकी जाति पूछेगा। मुझे उसके कमरे में रहने वाले उस साथी से डर लगता है जो उसके साथ भेदभाव करेगा। मुझे उसके कमरे के छत के पंखे से भी डर लगता है। हम भारत की जनसंख्या का एक चौथाई हैं, यानी 3 करोड़ लोग। जब जनगणना में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो हमारी गिनती की जाती है और फिर हमें दोबारा छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने 1948 में अपनी पुस्तक "अछूत" में हमारे पूर्वजों के बारे में लिखा था कि कुलीन वर्ग ने उन्हें (हमारे पूर्वजों को) पराजित जातियों के बिखरे हुए अवशेष माना और उन्हें गाँव के बाहरी इलाकों में धकेल दिया और वहाँ उन्हें घर बनाने की अनुमति दी। उन्हें बचा हुआ भोजन दिया। उन्होंने उन्हें ऐसे काम सौंपे जो कोई और नहीं करता था और उन्हें (पूर्वजों को) "अछूत" घोषित कर दिया।

संविधान लागू होने के सत्तर साल बाद भी हम दमन का शिकार हैं। हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ऐतिहासिक रूप से वंचित जैसे नाम देकर नए नाम दे दिए गए हैं। हमारे देश में शिक्षा सबसे महंगी है और उनमें भी, अगर हम मेडिकल, तकनीकी, कानून या सीए की पढ़ाई की बात करें, तो दलित समुदाय के लिए ये पढ़ाई बेहद मुश्किल है। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, रहने की जगह नहीं है, घर में बिजली नहीं है, माता-पिता के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, दलित समुदाय के माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित करके डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन सरकार ने अब 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल और तकनीकी शिक्षा के लिए एक परीक्षा शुरू कर दी है, जिसे मेडिकल के लिए NEET और तकनीकी के लिए JEE के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इन परीक्षाओं में गंभीर घोटाले हुए हैं और अमीर लोगों के बच्चे NEET और JEE देकर आगे बढ़ने लगे हैं। NEET में हुए गंभीर घोटालों से कई छात्रों को नुकसान हुआ है। यह नहीं माना जा सकता कि इसमें दलित समुदाय के छात्र नहीं हैं। संक्षेप में, आर्थिक रूप से सक्षम छात्र NEET परीक्षा उत्तीर्ण करके मेडिकल और JEE परीक्षा उत्तीर्ण करके तकनीकी इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने लगे। संक्षेप में, कक्षा 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होने लगा। क्योंकि NEET परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गलत उत्तरों पर अंक काटे जाने लगे। इस तरह छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ने लगा। इस अन्याय से न केवल एक समुदाय के बल्कि हर समुदाय के छात्र प्रभावित होने लगे, तो क्या कक्षा 12वीं के बाद NEET और तकनीकी इंजीनियरिंग के लिए JEE परीक्षा की कोई आवश्यकता है?

एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में गुजरात देशभर में तीसरे स्थान पर

▸▸ अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान गुजरात ने लगभग 44,041 करोड़ रुपए का भारी विदेशी निवेश आकर्षित किया

▸▸ राज्य के एफडीआई में आधे से अधिक यानी 52 प्रतिशत हिस्सा अकेले अहमदाबाद जिले का, तीन ही महीनों में 23,699 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त किया

▸▸ गुजरात ने गत 25 वर्षों में कुल 3,91,613 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश प्राप्त किया, देश में आए कुल निवेश का 15 प्रतिशत गुजरात में

▸▸ सेमीकंडक्टर तथा ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में गुजरात बना वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात 'विकसित भारत' के लिए 'विकसित गुजरात' के मंत्र के साथ प्रगति के नए शिखर पार कर रहा है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा घोषित ताजे आँकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने में गुजरात देशभर में तीसरे स्थान पर रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के नौ महीनों की समयावधि के दौरान गुजरात ने लगभग 44,041.7 करोड़ रुपए का भारी विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफलता पाई है। इन आँकड़ों से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुजरात देश के टॉप 3 राज्यों में अपना स्थान बनाए रखते हुए विदेशी निवेश के लिए सुरक्षित एवं प्रगतिशील गंतव्य सिद्ध हुआ है।

इस समयावधि के दौरान राज्य में आए एफडीआई में आधे से अधिक यानी लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा अकेले अहमदाबाद जिले का है। गुजरात ने केवल अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के तीन महीनों के दौरान ही 24,716 करोड़ रुपए का एफडीआई प्राप्त किया है, जिसमें सर्वाधिक 23,699 करोड़ रुपए का एफडीआई अहमदाबाद में प्राप्त हुआ है। यह दर्शाता है कि अहमदाबाद वैश्विक स्तर के बिजनेस सेंटर के रूप में उभर आया है।

दूसरे स्थान पर गांधीनगर में 590 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आया है। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी राज्य में विदेशी निवेश लाने में एक महत्वपूर्ण उद्दीपक के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा खेडा, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहाल, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वडोदरा, आणंद तथा नवसारी आदि जिले भी एफडीआई आकर्षित करने में सफल रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक यानी 25 वर्षों के दौरान गुजरात ने 3,91,613 करोड़ रुपए एफडीई प्राप्त किया है, जो देश में आए कुल एफडीआई का 15 प्रतिशत से अधिक होता है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गिफ्ट सिटी तथा धोलेरा एसआईआर जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण आगामी वर्षों में यह निवेश और भी बढ़ने की प्रबल संभावना है।

राज्य सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के कारण विशेषकर सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, फार्मा तथा रक्षा जैसे भावी क्षेत्रों में निवेशकों ने विशेष रुचि दिखाई है। उद्योग जगत के अग्रणी भी गुजरात की प्रो-एक्टिव सरकारी नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण परंपरागत क्षेत्रों के साथ सनराइज सेक्टर्स में भी बड़े अवसर सृजित हुए हैं।

गुजरात सरकार इस गति को बरकरार रखने तथा आगामी समय में एफडीआई क्षेत्र में पहला स्थान हासिल करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण एवं नई उद्योग नीतियाँ आगामी दिनों में रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाई पर ले जाएंगे।

प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की आवश्यकता

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे बुनियादी तंत्र यह है कि नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने का अधिकार है। लेकिन यह बुनियादी जवाबदेही तंत्र अब खो चुका है। आजकल, कई चुने हुए सांसद चुनाव के दौरान किए गए वादों के विपरीत काम करते हैं। इतना ही नहीं, वे उस पार्टी की सरकार का समर्थन करते हैं जिसके वे खिलाफ थे। कभी-कभी वे ऐसे विधेयकों का भी समर्थन करते हैं जो उनके मतदाताओं को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी-कभी या अक्सर, वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। फिर भी, अगले चुनाव तक या पांच साल तक कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, राज्य स्तर पर, स्विट्जरलैंड में और लैटिन अमेरिका के कुछ

हिस्सों में, निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार विभिन्न रूपों में मौजूद है। यदि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र के एक निश्चित प्रतिशत मतदाताओं को नए चुनाव कराने की अनुमति दी जाती है। यह राजनीतिक वर्गों के बीच आपसी टकराव पैदा करने की व्यवस्था नहीं है। प्रतिशत सीमाएं और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय ऐसी व्यवस्था को रोकते हैं। यह नागरिकों को निरंतर आधार पर अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने की व्यवस्था है। यह केवल मताधिकार का आवधिक प्रयोग नहीं है। भारत के कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में पहले से निर्वाचित पंचायत नेताओं को वापस बुलाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को विधायकों और सांसदों पर लागू न करने का कोई सैद्धांतिक कारण नहीं है। जो लोकतंत्र अपने नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता, वह केवल नाम का लोकतंत्र है।